आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 19.12.2022 से 24.12.2022)

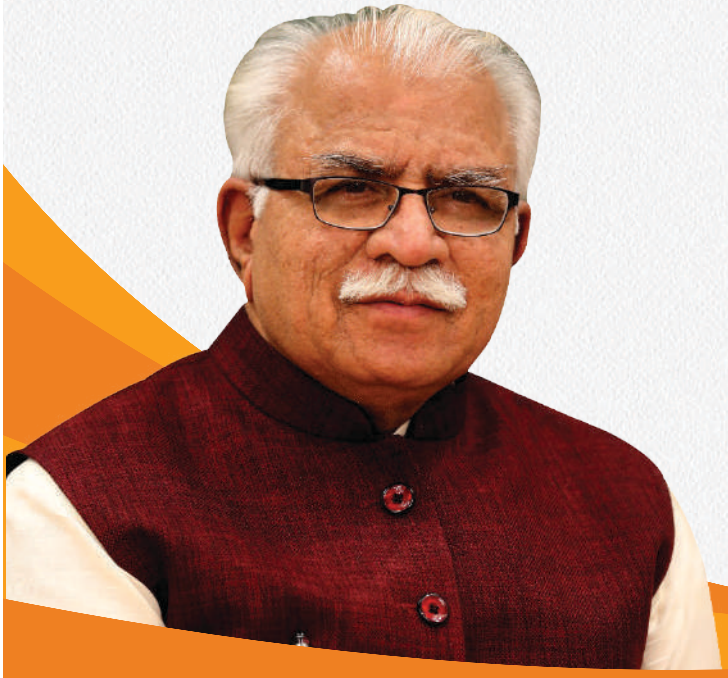

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

पंचकूला जिलें की विकास परियोजनाओं का औचक निरीक्षण

(दिनांक 19.12.2022)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला सेक्टर–19 में लगभग 30.54 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में तेजी लाएं ताकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह आरओबी जनता को समर्पित किया जा सके।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया कि पुल का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है केवल स्लैब डालने का कार्य बाकी है यह कार्य 20 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह आरओबी पंचकूलावासियों की लंबित मांग है और इसके पूरा होने पर पंचकूलावासियों विशेषकर सेक्टर. 19 के निवासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री जी ने इससे पूर्व सेक्टर–3 में लगभग 29 करोड़ रुपये की लागत से

बन रहे नगर निगम पंचकूला के कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ–साथ संबधित निर्माण एजंसी से कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संबधित एजंसी द्वारा निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष व नगर निगम के महापौर इस कार्य की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सरचार्ज माफी योजना का लाभ अब 31 दिसंबर 2022 तक

(दिनांक 19.12.2022)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई सरचार्ज माफी योजना–2022 को 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है।

इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था।

यह योजना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। साथ ही योजना के तहत लंबित बिलों को भुगतान करने वाले सरकारी कार्यालयों एवं विभागों को भी लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू कृषि उपभोक्ता और सरकारी ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है।

एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।

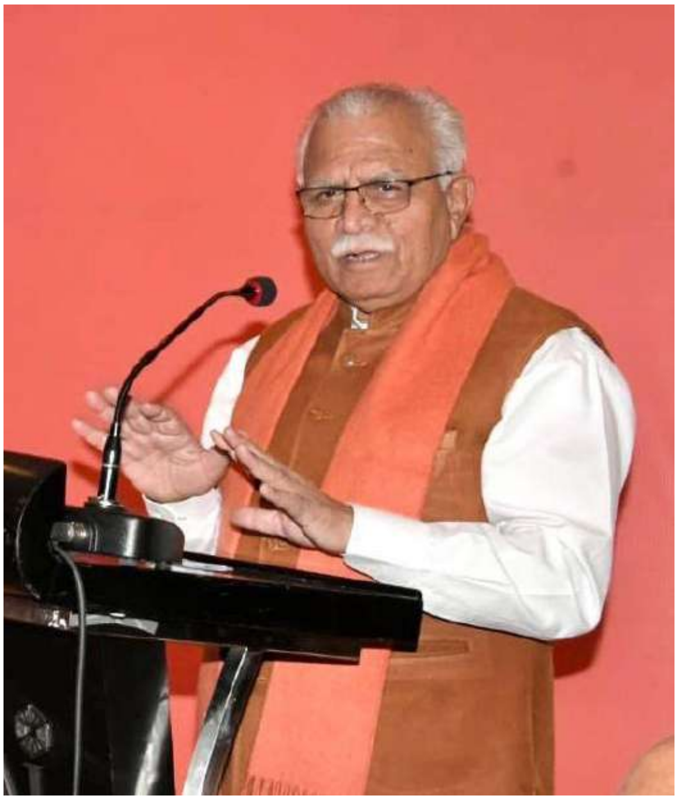

महाराजा शूर सैनी जयंती

(दिनांक 20.12.2022)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराजा शूर सैनी की जयंती के अवसर पर हिसार में सैनी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जन समूह को चंडीगढ़ से वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनों को सामाजिक समरसता का संदेश दिया। हरियाणा में वंचितों व जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार की ओर से अलग से मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सर्वे किया जा रहा है और जिनके पास आवास नहीं हैं ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किये जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने सैनी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के

जीर्णोद्धार व नव निर्माण के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 31 लाख रुपये देने की घोषणा की।

इसके अलावा उन्होंने सैनी समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फूले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने धर्मशाला के लिए जमीन देने की मांग पर घोषणा करते हुए कहा कि समाज के लोगों को आवेदन करना होगा और नियमानुसार धर्मशाला के लिए प्लॉट आवंटित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महाराजा शूरसैनी जयंती पर यह दूसरा राज्य स्तरीय समारोह है। महाराजा शूरसैनी बहुत ही प्रतापी वेदों के ज्ञाताए न्यायप्रियए धर्मात्मा एवं प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में पूर्ण समाजवाद था। उन्हीं के नाम पर शूरसैनी प्रदेश मथुरा के पास का इलाका कहलाया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश में अनेक संत.महात्माओंए ऋषि–मुनियों और गुरुओं ने मानवता को जीवन का सही रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज

की धरोहर हैं। उनकी विरासत को सम्भालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसी दिशा में हम संत–महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों के संदेश को जन–जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महाराजा शूरसैनी जयंती समारोह का आयोजन भी इसी योजना की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि सैनी समाज कर्मशील समाज है। उनके सामने किसी भी प्रकार की कठिनाई या बाधा आती है तो वे उसका डटकर सामना करते हैं। इसलिए कभी भी किसी को भी अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचाने देना चाहिए। यदि कोई कुछ मुफ्त देने की बात कहता है तो यह समझना चाहिए कि सबसे पहले इसका अधिकार अंत्योदय का है। इसलिए जन कल्याण में सर्व समाज के लोग सरकार के साथ भागीदार बनें। समारोह में सैनी समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोक कलाकारों ने महाराजा शूर सैनी के इतिहास और उनकी वीरता की गाथा को गीतों के माध्यम से बयां कियाए जिसे सुनकर यहां आए लोगों का उत्साह ओर भी बढ़ गया।

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे पर चंदावली गांव में बनेगा आरयूबी

(दिनांक 20.12.2022)

प्रभाव : दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फरीदाबाद के बल्लभगढ–मोहना रोड पर चंदावली गांव के पास अंडर ब्रिज की समस्या का मंगलवार को मुख्यमंत्री व केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद समाधान हो गया। अब यहां पर एक्सप्रेस वे के नीचे से आरयूबी का निर्माण किया जाएगा और यह आरयूबी दिल्ली– आगरा कैनाल पर बने पुल की चौड़ाई का ही बनाया जाएगा।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर डिजाईन के दौरान चंदावली गांव के सामने आरयूबी का प्रावधान नहीं हो पाया था। इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। करीब 20 गांव के ग्रामीणों को बल्लभगढ़ आने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडक़री से बातचीत की व पत्राचार भी किया। उन्होंने बताया कि अब केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री ने इस समस्या के समाधान के लिए चंदावली गांव के सामने बल्लभगढ–मोहना रोड पर रोड अंडर ब्रिज बनाने को मंजूरी दे दी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

(दिनांक 22.12.2022)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्थित सभी आंगनवाडियों का डाटा ऑनलाइन अपडेट करें। तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की उपयोगिता के मामले में प्रदेश को ऐसा मॉडल बनाएं ताकि अन्य राज्य भी अनुसरण कर सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 6 साल तक बच्चों उन केंद्रों को संचालित करने वाले वर्करस तथा वहां काम करने वाली हैल्पर्स की उपस्थिति भी प्रतिदिन ऑनलाइन लगेगी। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कस को यथाशीघ्र मोबाइल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि वे अपने केंद्र के डाटा को अपडेट रख सकें। उक्त सभी का डाटा परिवार पहचान पत्र से जोडने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे बच्चों को समय पर न्यूट्रिशियन देने टीकाकरण करने पौष्टिक आहार देने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि डाटा अपडेट होने से केंद्र व राज्य सरकार की बच्चों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में भी आसानी होगी।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात

(दिनांक 24.12.2022)

प्रभाव : मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और कई योजनाओं की तारीफ भी की।

इन योजनाओं में मुख्य रूप में परिवार पहचान पत्र योजना जिसके माध्यम से

साप्ताहिक सूचना पत्र

आज हर नागकिर को घर बैठे ही बिना किसी परेशानी के सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

इसी प्रकार 1 जनवरी 2023 से पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक बीपीएल राशन कार्ड बनने की योजना की से प्रधानमंत्री को अवगत करयाए जिसकी उन्होंने सराहना की।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वामित्व योजना लागू किए जाने के संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के साथ हरियाणा में बनाये जा रहे जंगल सफारी के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रधानमंत्री जी को इस जंगल सफारी के शिलान्यास के लिए हरियाणा आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेले के उद्घाटन अवसर पर आने के लिए भी प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया गया है। इतना ही नहीं जी–20 के सदस्यों को भी सूरजकुंड मेले में आमंत्रित किया जाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

सुशासन दिवस

(दिनांक 24.12.2022)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की।

उन्होंने अपने अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए एक बार फिर नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें स्वचालित राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टलए जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द कॉपी मुफ्त पासपोर्ट योजनाए एचपीएससी मांग पोर्टल एचएसवीपी के तहत सभी सेक्टरों में नागरिक सुविधा केंद्र और कार्य शिकायत निवारण प्रणाली शामिल हैं।

सुशासन दिवस के इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद किया। मुख्यमंत्री जी ने उनके डिजिटल हरियाणा के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान

साप्ताहिक सूचना पत्र

डिजीटली माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री जी ने 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इनमें गुड गवर्नेंस के लिए स्टेट लेवल अवार्डस तथा स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्डस् शामिल हैं। आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए इ–गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये गए हैं।

जिन नई योजनाओं की शुरुआत आज कि गई है उसमे महत्वपूर्ण योजनाएं

स्वचालित राशन कार्ड योजना

बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा का शुभारंभ किया।एक बार फिर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनते हुए हरियाणा अब राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस लॉन्च के साथ सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है।

लाभार्थियों को राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र, ई–दिशा आदि से या स्वयं भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकें।

हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जिससे इस योजना में 12,46,507 बीपीएल् परिवार शामिल हुए और अब कुल संख्या 30.38 लाख हो गई है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त पासपोर्ट योजना

हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है।

पासपोर्ट का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल https://passport.higheredu hry.ac.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। निरूशुल्क पासपोर्ट योजना की शुरुआत के बाद अब उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा केंद्रीकृत तरीके से पासपोर्ट शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह योजना इच्छुक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेशों में अन्य अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द

राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी 143 तहसीला, उप–तहसीलों में वैब–हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है।

इसके बावजूद किसान को जमाबंदी के प्रिंट को पटवारी से सत्यापित करवाना पड़ता है जिससे उसे असुविधा का सामना करना पड़ता है। परंतु अब किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। जमाबंदी की यह प्रति कानूनी रूप से मान्य होगी।

एचपीएससी मांग पोर्टल

यह पोर्टल सार्वजनिक विज्ञापन के लिए नई मांग करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगा। विभागीय नोडल अधिकारी नई मांग ऑनलाइन भरेंगे और संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव लॉगिन के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी को भेजेंगे। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ ही

एचपीएससी मांग के विरुद्ध विभाग को प्रश्न पूछ सकता है विभाग जवाब देने और पोर्टल पर ही प्रश्नों का समाधान कर सकेंगे। एचपीएससी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए विभाग को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजे जाएंगे। एचपीएससी और विभाग पोर्टल पर मांग की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।

नागरिक सुविधा केंद्र नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल

यह नागरिक सुविधा केंद्र सीएफसी राज्य के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी नागरिकों से संबंधित मुद्दों के लिए वन–स्टॉप सॉल्यूशन होगा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसवीपी के सभी सेक्टर में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। यह केंद्र सामान्य सेवाओं के साथ–साथ शहरी विकास और शहरी मुद्दों से संबंधित नागरिक–केंद्रित सेवाएं प्रदान करेंगे।

प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 वर्कस्टेशन शामिल होंगे जिनमें प्रभावी संचार और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक सेवा विशेषज्ञ नियुक्त किए

जाएंगे। नागरिकों को टोकन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

8 जिलों में 177 कॉलोनियों को किया गया नियमित

मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा कि आज 8 जिलों में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने 2 वर्ष पहले आवेदन मांगे थे और सर्वे करने के बाद 845 ऐसी कॉलोनियों की पहचान की गई।

इन कॉलोनियों में अस्थाई रूप से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी बनाई गईए ताकि वहां आवश्यक कार्य करवाए जा सकें। इन्हीं कॉलोनियों में से आज 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया गया है।

पुलिस एनफोर्समेंट विंग का किया जाएगा गठन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोनीपत

को नई पुलिस कमिश्नरी बनाने तथा अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस का कार्य प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ अन्य कार्य जैसे खनन सिंचाई बिजली अवैध कब्जों को हटाना इत्यादि भी उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसलिए अब राज्य सरकार ने अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके थाने भी अलग होंगे और इसके संचालन के लिए अलग से एडीजीपी एनफोर्समेंट पद भी

सृजित किया जाएगा।

वर्क्स शिकायत निवारण प्रणाली

वर्क्स शिकायत निवारण प्रणाली नागरिकों और ठेकेदारों द्वारा शिकायतों को उठाने के लिए वन–स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने कार्य की

गुणवत्ता में सुधार और समय–सीमा के पालन और भ्रष्टाचार पर जांच करने का अवसर देना है।

इस प्रणाली से नागरिक कार्य की गुणवत्ता में कमी और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा ठेकेदार भी बिलिंगए भुगतान और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। बिलिंग और भुगतान से संबंधित शिकायतों को टेंडर आमंत्रित करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के पास भेजा जाएगा।

यदि अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती हैए तो सिस्टम द्वारा शिकायत को अगले उच्च अधिकारी तक पहुँचाया जाएगा। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सतर्कता विभाग के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2023 का कैलेंडर और मैनुअल प्रक्रिया नियमावली का भी विमोचन किया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने 2023 के वर्ष

साप्ताहिक सूचना पत्र

को अंत्योदय अरोगय वर्ष भी घोषित किया। जिसके तहत गरीब परिवार बीमार न पड़े और उनकी आर्थिक उन्नति हो सके इस दिशा में सरकार दुगनी रफ़्तार से कार्य करेगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जनता की भी राय होनी चाहिए कि कौन अधिकारी व कर्मचारी सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरी होती है और जनता ही जन प्रतिनिधियों को चुनती है इसलिए इनकी राय भी सरकारी तंत्र में ली जानी चाहिए। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के कामकाज की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

इसके साथ ही सुशासन उनके लिए महज़ एक शब्द नहीं बल्कि संकल्प है। जवाब देह पारदर्शी और संवेदनशील सरकार का। उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे है।